

for the initial three days of default and at the rate of rupees ten thousand per day for each day of default thereafter:

Provided that where the proper officer is satisfied with the reasons of delay, he may waive off the charges referred to in the second proviso to sub-section (3) of section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(4) No charges for late presentation of Bill of Entry shall be liable to be paid where the entry inwards or arrival of cargo, as the case may be, has taken place before the date on which the Finance Bill, 2017 receives the assent of the President."

[F.No.450/32/2016-Cus IV]

SHAIFALI G. SINGH, Under Secy.

Note : The Principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide notification number G.S.R.838(E), dated the 25th November,2011 and last amended vide notification number 45/2016- Cus(N.T.) dated 01.04.2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च,2017

सं. 27/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.324(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 46 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, बिल ऑफ एंट्री (फार्म्स) रेग्यूलेशन, 1976 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का नाम बिल ऑफ एंट्री (फार्म्स) संशोधन रेग्यूलेशन, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बिल ऑफ एंट्री (फार्म्स) रेग्यूलेशन, 1976 में विनियम 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को अंत:-स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"विनियम 4(1) आयातक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके पास कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2013, के अंतर्गत वैध लाइसेंस है, उस दिन जब वस्तुओं को ले जाने वाला हवाई जहाज अथवा वैसल अथवा व्हीकल उस कस्टम स्टेशन पर पहुंचता है जिस पर ऐसी वस्तुओं की घरेलू उपभोग अथवा वेयरहाउसिंग के लिए निकासी की जानी है, से अगले दिन के अंत से पूर्व (अवकाश वाले दिन को छोड़कर) बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां कहीं बिल ऑफ एंट्री उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत नहीं की जाती है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं थे तो आयातक बिल ऑफ एंट्री के देर से प्रस्तुत किए जाने के लिए आरंभ के 3 दिन की चूक के लिए 5 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से और इसके पश्चात चूक के लिए 10 हजार रुपए प्रतिदिन के दर से प्रभार अदा करने का दायी होगा:

बशर्ते कि यहां कहीं समुचित अधिकारी विलंब के कारणों से संतुष्ट है तो वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक में संदर्भित प्रभार को माफ कर सकता है।

(3) ऐसे मामलों में बिल ऑफ एंट्री के देरी से प्रस्तुत किए जाने में कोई भी प्रभार अदा नहीं किया जाना होगा,जहां एंट्री इनवार्ड, विल्ट विधेयक, 2017 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व हो चुका है।"

[फा. सं. 450/32/2016-सीमाशुल्क (IV)]

शैफाली जी. सिंह, अवर सचिव

नोट : प्रधान विनियम को अधिसूचना सं. 396-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 1 अगस्त, 1976 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना सं. 03/88-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 14 जनवरी, 1988 के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया था, अपितु बाद में अधिसूचना सं. 77/89 दिनांक 27 दिसंबर 1989 के अंतर्गत इसकी पुनः बहाली की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

No. 27/2017-Customs (N.T.)

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 46 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Bill of Entry(Forms) Regulations, 1976, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bill of Entry (Forms) Amendment Regulations, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bill of Entry(Forms) Regulations,1976, after regulation 3,the following regulation shall be inserted, namely;

“Regulation 4. (1) *The importer or a person authorised by him who has a valid licence under the Customs Broker Licensing Regulations, 2013, shall present the bill of entry before the end of the next day following the day (excluding holidays) on which the aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at a customs station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehousing.*

(2) Where the bill of entry is not presented within the time specified in sub-regulation (1) and the proper officer of Customs is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, the importer shall be liable to pay charges for late presentation of the bill of entry at the rate of rupees five thousand per day for the initial three days of default and at the rate of rupees ten thousand per day for each day of default thereafter:—

Provided that where the proper officer is satisfied with the reasons of delay, he may waive off the charges referred to in the second proviso to sub-section (3) of the section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(3) No charges for late presentation of Bill of Entry shall be liable to be paid where the entry inwards or arrival of cargo, as the case may be, has taken place before the date on which the Finance Bill, 2017 receives the assent of the President.”

[F.No.450/32/2016-Cus IV]

SHAIFALI G. SINGH, Under Secy.

Note : The principal regulation was published vide notification number 396-Cus(N.T.) dated 1st August, 1976, superceded by notification number 03/88-Cus(N.T.) dated 14th January,1988 but then restored by notification number 77/89 dated 27th December,1989.